जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की हैं उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की है।
– अज्ञात

कैंसर से मुठभेड़

शोध और अध्ययन को बढ़ावा मिल सके। समिति ने मुंबई स्थित टाटा मेमोरियल कैंसर शोध एवं उपचार केंद्र के नेटवर्क को देशव्यापी बनाने की सिफारिश की। देश में पिछले कुछ समय में कैसर की बीमारी तेजी से फैली है।

मनमोहन

एक संसदीय समिति ने बढ़ते कैंसर के मामलों से निपटने के लिए देश भर में विशिष्ट इलाज केंद्र (ट्रीटमेंट हब) बनाने की सिफारिश की है ताकि मरीजों को एक ही जगह इलाज की सभी सुविधाएं मिल सकें और उन्हें लंबी दूरी तय कर इलाज के लिए महानगरों में न जाना पड़े। विज्ञान एवं तकनीक, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने सोमवार को इस संबंध में अपनी रिपोर्ट राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को सौंप दी। समिति ने देश में कैंसर के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई और कहा कि इस बीमारी से पीड़ित मरीजों में करीब 68 प्रतिशत मृत्यु दर बेहद दुखद है।

उसने कहा कि वर्तमान में देश में कैंसर के इलाज का जो नेटवर्क है, वह बढ़ती बीमारी को देखते हुए बहुत छोटा और अपर्याप्त है। आज इसके लिए एक मजबूत और विशाल तंत्र की जरूरत है जो कैंसर की दवाओं के मूल्य को नियंत्रित रखे। यही नहीं सरकार को सीएसआर (कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी) फंडिंग के लिए विभिन्न फर्मों से समझौता करना चाहिए ताकि इस संबंध में शोध और अध्ययन को बढ़ावा मिल सके। समिति ने मुंबई स्थित टाटा मेमोरियल कैंसर शोध एवं उपचार केंद्र के नेटवर्क को देशव्यापी बनाने की सिफारिश की। देश में पिछले कुछ समय में कैसर की बीमारी तेजी से फैली है।

अक्टूबर में संसदीय समिति को हेल्थ मिनिस्ट्री ने जानकारी दी थी कि हर साल कैंसर के करीब 16 लाख नए मामले आ रहे हैं। सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि इस बीमारी के इलाज की बेहतर सुविधाएं देश के कुछ ही हिस्सों में सीमित हैं। यही नहीं इसका इलाज बेहद महंगा है। छोटी जगहों पर तो कई बार बीमारी का पता ही नहीं चलता या देर से पता चलता है। फिर दूर–दराज के इलाकों से लोग महानगरों में इलाज के लिए आते हैं। जितना खर्च इलाज में होता है, उतना ही शहरों में मरीजों के परिजनों के रहने पर होता है। यही नहीं कई बार बड़े शहरों में एम्स जैसे अस्पताल में इलाज के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

मरीज का नंबर आते–आते बीमारी गंभीर रूप ले लेती है और मरीज की जान चली जाती है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि छोटी–छोटी जगहों पर जांच और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सुविधा हो। आज भी इस बीमारी के स्पेशलिस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्यादा हैं, जिनकी फीस देना गरीब लोगों के लिए संभव नहीं है। इसलिए कई लोगों ने यह भी सुझाव दिया है कि कैंसर का ट्रीटमेंट सिर्फ सरकारी अस्पतालों में हो, प्राइवेट सेक्टर को इससे बाहर कर दिया जाए। हालांकि यह संभव नहीं है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इस संसदीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए कैंसर के इलाज के लिए देश भर में एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी।

स्वास्थ्य में ही ऊर्जा

ब्रह्म कुमारी

धर्म-दर्शन

अच्छी सेहत के लिए जितना जरूरी स्वच्छ और संतुलित खानपान है, उतना ही जरूरी ये भी है कि आप किन लोगों के साथ उठते–बैठते हैं, किस वातावरण में रहते हैं और साथ ही अपने आसपास के लोगों का कितना सम्मान करते हैं।

यह बुद्धिमता से परिपूर्ण एक ऐसा लोकप्रचलित तथ्य और है जिसे आज के जमाने में भुला दिया गया है, या जिसकी महत्ता पर अब ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता।

वर्तमान समय में हमारे समाज की जो स्थिति है, उसके मद्देनजर यह कहना गलत तो नहीं होगा कि हम अस्वस्थ जीवनशैली, अस्वस्थ खानपान के प्रति आकर्षित होने लगे हैं, जहां हम घर के खाने की जगह फास्ट फूड और चीनी से भरे भोजन करते हैं, कम सोते हैं, न्यूनतम व्यायाम करते हैं, साथ ही ना तो हमारे पास किसी से बात करने का समय है। हम बस चिंता करने में ही मशगूल रहते हैं।

संपादकीय

हिमालय की पुकार

हिमालयी राज्यों का अपने मिजाज और हितों को लेकर एकजुट होना खुद में एक स्वागतयोग्य पहल है। उत्तर–पूर्व के आठ और उत्तर–पश्चिम के तीन, यानी हिमालय की जद में आने वाले कुल ग्यारह राज्यों की समस्याएं और संभावनाएं काफी कुछ एक–सी हैं। इसे ध्यान में रखते हुए बीते रविवार को इनके शीर्ष प्रतिनिधियों का पहला सम्मेलन मसूरी में हुआ, जिसमें केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने भी भागीदारी की। सम्मेलन में जाहिर की गई कई चिंताएं पहले से देश की नजर में रही हैं लेकिन राष्ट्रीय चर्चा का विषय ये कभी नहीं बन पाईं। जैसे, ठेठ पहाड़ी गांवों से उखड़कर लोगों का मैदानी इलाकों में चले आना। गांव के गांव खाली या उनमें सिर्फ बुजुर्गों का वास। ध्यान रहे, देश की उत्तरी सीमा के उस पार ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। वहां काफी पहले से निर्जन चले आ रहे सीमावर्ती इलाकों में भी नई चीनी बस्तियां बस रही हैं क्योंकि एक तो चीन को तिब्बत पर हर हाल में अपना वर्चस्व सुनिश्चित करना है, दूसरे पहाड़ के प्राकृतिक संसाधनों का सार्थक उपयोग करना चीनी हुकूमत को अच्छी तरह आता है। उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की मांग वहां विकास का पर्वतीय मॉडल विकसित करने से जुड़ी थी लेकिन आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बैठकर देखें तो सारा सरकारी ढर्रा मैदानी ही दिखता है। पता नहीं यह स्थिति कभी बदलेगी या नहीं लेकिन इसकी रोशनी में जो प्रस्ताव मसूरी सम्मेलन में पारित हुए, उसमें दो बहुत ठोस हैं। एक यह कि पर्यावरण से जुड़ी जिम्मेदारियों और बाध्यताओं की भरपाई के लिए हिमालयी राज्यों को केंद्र की ओर से कुछ श्ग्रीन बोनसश दिया जाए, और दूसरा यह कि इन राज्यों के लिए केंद्र में एक अलग मंत्रालय बनाया जाए।

सदन के गणित पर ध्यान दें तो तीन तलाक विधेयक पारित होने के पीछे कुछ पार्टियों के वॉकआउट, कुछ के मतदान बहिष्कार और कुछ के बिना घोषणा के ही वोटिंग में हिस्सा न लेने की बड़ी भूमिका रही है।

संसद बीजेपी के हाथ

सीमा सिंह

पहले सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, फिर तीन तलाक बिल को राज्य सभा से पारित कराकर नरेंद्र मोदी की सरकार ने संसद के दोनों सदनों में अपने वर्चस्व का सबूत दे दिया है। खासकर तीन तलाक बिल को एक पोलराइजिंग इश्यू की तरह लिया जा रहा था। समाज से लेकर राजनीति तक इस पर तीखा विभाजन देखा जा रहा था। राज्य सभा में बीजेपी की ताकत इधर तेजी से बढ़ी है, लेकिन अपने घोषित सहयोगियों को मिलाकर भी यहां वह बहुमत से अभी काफी दूर है। इसके बावजूद अपने तीखे टकराव वाले बिल भी अगर वह यहां से पास करा ले जा रही है तो यह उसके फ्लोर मैनेजरों के लिए शाबाशी की और विपक्ष के लिए चिंता की बात है। सदन के गणित पर ध्यान दें तो तीन तलाक विधेयक पारित होने के पीछे कुछ पार्टियों के वॉकआउट, कुछ के मतदान बहिष्कार और कुछ के बिना घोषणा के ही वोटिंग में हिस्सा न लेने की बड़ी भूमिका रही है। इसके अलावा कांग्रेस, एनसीपी, आरजेडी आदि के कुछ सामान्य और कुछ जाने–माने सांसद भी वोटिंग के दिन सदन में नहीं आए तो इन पार्टियों को इसकी वजह पता करनी चाहिए। संसद में चली बहस की शक्ल कुछ ऐसी थी जैसे इस

विधेयक को लेकर हां या ना जैसा कोई बंटवारा ही न हो।

विरोधी पक्ष का कहना था कि पारिवारिक विवाद को आपराधिक दायरे में ले जाना ठीक नहीं, फिर भी सरकार इस मामले में कानून लाना चाहती है तो विधेयक को सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाए ताकि उसके खुरदुरे पहलुओं को दुरुस्त करके सहमति का दायरा बढ़ाया जा सके। यह जिम्मेदारी मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की थी कि इस राय के पक्ष में वह अधिक से अधिक दलों और निर्दलीय सांसदों को गोलबंद करे। लेकिन कांग्रेस की अपनी समस्याएं ही इतनी ज्यादा हैं कि औरों की कौन कहे, उसके खुद के मौजूदा राज्य सभा सांसदों में से भी पांच ने वोटिंग से अलग रहना ठीक समझा। तो क्या लोकसभा के बाद राज्य सभा में भी, यानी समूची संसद पर बीजेपी के वर्चस्व को अब इतना पक्का मान लिया जाए कि अपनी मर्जी से वह कोई भी कानून बनवा सकती है? यह संदेश पार्टी के जनाधार में पहुंचने लगा है।

गनीमत है कि विश्व हिंदू परिषद का शीर्ष पद अभी प्रवीण तोगड़िया नहीं संभाल रहे, वरना अयोध्या में राम मंदिर के लिए कानून लाने की मांग अब तक वीएचपी तेज कर चुकी होती। बीजेपी के रणनीतिकार अपने मुद्दों को असमय खत्म कर देने की गलती अतीत में दो बार कर चुके हैं। एक बार बाबरी मस्जिद ढहाने और दूसरी बार सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री न बनने देने पर अड़ जाने के रूप में। यह गलती वे तीसरी बार नहीं करने वाले। मुद्दे धीरे–धीरे पकें, उबाल मारकर चूल्हा ही न बुझा दें, फिलहाल यही उनकी रणनीति है। इसलिए संसद पर पकड़ के बावजूद उथल–पुथल मचा देने वाले किसी कानून की उम्मीद उनसे न करें।

सूडोकु नवताल- 5144

कठिनतम

				6	8	5		
	1						2	
		2						8
			4					9
6				5				1
2					3			
5						3		
	8						6	
		4	9	1				

Jagrutidaur.com, Bangalore

■ प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
■ प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
■ पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते .
■ पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5143 का हल

2	4	6	7	9	3	5	8	1
3	1	5	2	8	6	4	7	9
7	8	6	1	5	4	2	3	6
6	5	7	9	3	8	1	4	2
9	3	1	4	7	2	8	6	5
4	2	8	6	1	5	7	9	3
1	9	2	3	4	7	6	5	8
5	7	3	8	6	1	9	2	4
8	6	4	5	2	9	3	1	7

अपना ब्लॉग

राजभवन ने सिर्फ भेजा न्योता, नसीब हुआ न भोज!

प्रभुनाथ शुक्ल। महाराष्ट्र में अंततः राज्यपाल की अनुशंसा के बाद राष्ट्रपति शासन लग गया। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी शिवसेना और एनसीपी को सरकार बनाने का चौबीस घंटे का वक्त दिया था। लेकिन दोनों दल समय सीमा के भीतर विधायकों की सूची उपलब्ध नहीं करा पाए। हालांकि जिस तरह के हालात वहां हैं, उसमें यह समय पर्याप्त नहीं था। क्योंकि राज्य के हालात को देखते हुए विपरीत विचाराधारा के दलों का बगैर कॉमन मिनिमन प्रोग्राम के एक साथ आना आसान नहीं था। राजभवन ने जो रणनीति बनाई थी, आखिरकार उसी की तरफ सधे कदम उठाए। राज्यपाल यह साबित करना चाहते थे कि उन्होंने पूरे संविधानिक नियमों का अनुपालन करते हुए पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी बरती। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद सोनिया गांधी के दूत अहमद पटेल, वेणुगोपाल, खड्गे और छगन भुजबल किसी नतीजे पर अभी तक नहीं पहुंच पाए। कांग्रेस और एनसीपी किस तरह का समझौता करना चाहती हैं। सोनिया गांधी की झंडी मिल गयी है। लेकिन अब शिवसेना क्या करती है यह वक्त बताएगा।